[श्री मोहम्मद अमीन]

इसका बिल्कुल साफ मतलब हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी बेइन्साफी की । इसलिए मैं नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से यह दर्खास्त करता हूं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रूल में तरमीम की जाए और इसको दुबारा रिकोगनाइज कर दिया जाए ।

Japanese offer of assistance for warmemorials in Manipur .

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manjpux); Sir, my special mention is regarding availability of external assistance for Manipur. Manipur is economically and industrially a poor State. In the Second World War the INA and Japanese | troops; advanced upto Manipur and hoisted the national flag at Moirang in j Manipur in early 1944. During the war j thousands of INA and Japanese soldiers j were killed by the Allied Forces, In memory of those killed in Manipur the Japanese and other memorial service j groups offered to establish a hospital, a | peace memorial hall and an industrial institute in Imphal in 1984 at an estimated cost of Rs. 32 crores then. But the then Union Government did not accord approval because of the prevailing situation in Manipur due to the extremist movement. Recently the Government of Manipur made a request for economic cooperation by providing technical assistance to Manipur through proper protocol. In the second week of August 1990 the Japanese Ambassador in India visited Manipur and the old offer of 1984 for economic cooperation and technical assistance was renewed. The Government and the people of Manipur are feeling restive on account of the delay taken by the Union Government in according approval. I urge upon the Union Government through this House, through you, to understand the feelings of the people of Manipur and accord approval at an early date. The Annual Plan Outlay for Manipur for the 1990-91 is only Rs. 170 crores. Now the assistance by the Japanese Government will come to around Rs. 70 crores. So this will be of very great help for the development of Manipur. I, therefore, urge upon the Government to kindly accord approval for that external assistance. Thank you.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित): वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में इस वक्त धान काफी मंडियों में आया हुआ है लेकिन वहां किसान का धान उठाया नहीं जा रहा है यहां तक कि सड़कें रोकने की नौबत आयी हुई है । कई जगहों पर तो यह बहुत देर से चल रहा है लेकिन सरकार इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है । इसकी वजह यह है कि जो सरकारी एजेंसियां खरीद करने वाली हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्ट प्रेक्टिसज की वजह से धन लेना चाहते हैं । वहां जो सेलर्ज हैं वे मालिक से जब राइस खरीदते हैं तो उनके रेट तय किये हुए होते हैं । इससे किसान का पैसा कट जाता है ।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

पर-मीट्रिक टन सेलर की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से डी. एफ. सी. को देना पड़ता है और डी. एफ. एस. ओ. को पर-टन के हिसाब से देना पड़ता है । इस हिसाब से जो उनके रेट तय हुए हैं यह किसान के जेब से जाते हैं । इस कारण किसान को मुश्किल का सामना करना पड़ता है । इस वक्त जो स्पेसिफिकेशन इस साल एफ. सी. आई. ने तय किये हैं वह पिछले साल और उसके पिछले साल से बहुत ज्यादा सख्त हैं जिसकी वजह से डी. एफ. सी. के आफिशियल धान नहीं उठा रहे हैं । इसलिए सरकार को यह चाहिए कि इन स्पेसिफिकेशन को हटाकर वही कर देना चाहिए जो पिछले सालों में था ।

यह धान एकदम से उठाया जाय, सारा धान उठाया जाय । वहां पर धान उठाने के लिए जो मशीनरी है वह इतनी करप्ट है कि अगर उनको कुछ दे देते हैं तो वे स्पेसिफिकेशन के लिए कोई बहाना बनाकर लूट करते हैं । इसलिए एकदम से इंस्ट्रक्शन्स जानी चाहिए कि किसानों का धान जितना भी मंडियों में है उसको स्पेसिफिकेशन को रिलेक्स करके वहां से उठाया जाय ।